पाकिस्तान और रूस: सहयोग का एक नया युग

डॉ. स्मिता तिवारी[*]

हाल के महीनों में, पाकिस्तान और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियां दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पुनर्संतुलन की ओर इशारा करती हैं। दोनों देशों के बीच हाल ही में संपन्न रक्षा सहयोग करार को, जो अपनी तरह का पहला करार है, उनके संबंधों में एक 'नई उपलब्धि' के रूप में निरूपित किया गया है। इस करार में राजनीतिक-सैन्य मुद्दों पर सूचना का आदान-प्रदान; अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहयोग; आतंक विरोधी और हथियार नियंत्रण कार्यकलापों में तेजी लाना; शिक्षा, दवाइयां, इतिहास, स्थलाकृति/टोपोग्राफी, जल-सर्वेक्षण/हाइड्रोग्राफी और संस्कृति सहित विभिन्न सैन्य क्षेत्रों में सहयोग सुदृढ़ करना; और शांति सेना अभियानों में अनुभव साझा करने की व्यवस्था है। पाकिस्तान को रूस द्वारा ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक अरब अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला का भी प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले, एमआई-35 हमलावर हेलिकाप्टरों की बिक्री के साथ ही, पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध समाप्त करने का रूस का निर्णय पुनर्संयोजित हुई विश्व (व्यवस्था) में निकट आने की दोनों देशों की इच्छा को प्रदर्शित करता है। क्या यह सहयोग के एक नए युग का संकेत है?

पाकिस्तान ओर रूस के बीच की दोस्ती अभी कुछ ही वर्षों पहले तक 'कल्पनातीत' थी जब दोनों देश शीतयुद्ध के दौरान एक दूसरे के विरोध में अलग-अलग गुटों में रहते थे। पाकिस्तान अमरीका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का हिस्सा था, जबकि पूर्व सोवियत संघ भारत को सैन्य तथा अन्य कूटनीतिक सहायता प्रदान किया करता था। पाकिस्तान ने पूर्व सोवियत संघ पर निगरानी रखने के लिए अमरीका को अपनी धरती का उपयोग करने की अनुमति दी थी और वह अफगानिस्तान में सोवियत बलों के विरूद्ध संघर्षरत मुजाहिद्दीन/तालिबान ताकतों को सैन्य प्रशिक्षण दिया करता था। इसके विरोध में पूर्व

सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार/वीटो का उपयोग करके भारत के विरूद्ध पाकिस्तान की हरेक चाल असफल कर रहा था। यह संतुलन बिलकुल स्पष्ट और सुदृढ़ था। शीतयुद्ध की समाप्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक परिवर्तनों के साथ ही दोनों देशों के बीच की कड़वाहट कम होनी शुरू हो गई थी। तथापि, संदेह के बादल पूरी तरह से नहीं छटे थे और तालिबान का मसला उभरकर इनके संबंधों के बीच आ रहा था।

यह केवल पिछले दो वर्षों में हुआ है कि दोनों देश अपने मतभेदों को दूर करने में कामयाब रहे हैं और एक-दूसरे से संपर्क/बातचीत की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। शीतयुद्ध (की समाप्ति) के बाद के युग में राष्ट्रीय हितों को पुन:परिभाषित करना निश्चित रूप से एक प्ररेणादायी कारक रहा है। चूंकि पिछले दो वर्षों से अमरीका भारत का 'कार्यनीतिक साझेदार' रहा है और सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस के स्थान पर आ गया है, इसलिए रूस के लिए भी इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ संपर्क कायम करना स्वाभाविक था। इसी प्रकार, अमरीका-पाकिस्तान संबंधों में ऐबटाबाद की घटना के बाद से शिथिलता आई है, जिसने पाकिस्तान को अमरीका पर अपनी निर्भरता कम करने का एक अच्छा कारण दे दिया है। पाकिस्तान और रूस के बीच सहयोग इस तथ्य द्वारा भी संचालित है कि जहां रूस हथियार तथा ऊर्जा संबंधी उत्पादों के व्यापार के लिए दक्षिण की ओर रूख कर रहा है, वहीं पाकिस्तान पहले से ही एक सक्षम लेकिन राजनीतिक रूप से "संचालनीय" व्यापार तथा निवेश सहयोगी की तलाश में है। पाकिस्तान की सुरक्षा तथा ऊर्जा आवश्यकताओं को समझते हुए यह तर्कसंगत है कि पाकिस्तान इस अवसर का लाभ उठाए। पाकिस्तान के लिए, रूस के साथ हथियार व्यापार इसे अमरीका की ओर से पड़ने वाले कार्यनीतिक दबावों को दूर करने और भारत की सामरिक अनुकूल परिस्थिति को कम करने में सहायता करेगा।

पाकिस्तान में रूस की रूचि का एक और महत्वपूर्ण कारण अफगानिस्तान की प्रकट होती स्थिति है, जिसके रूस की सुरक्षा से प्रत्यक्ष संबंध हैं। अफगानिस्तान के फिर से तालिबान के शासन के अधीन आने की संभावनाओं के संबंध में चिन्ताएं बनी हुई हैं। यदि अफगानिस्तान सुस्थिर हो जाता है तो यह पाकिस्तान, मध्य एशिया और रूस के बीच व्यापार के विस्तार का मार्ग खोल देगा। चूंकि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) बल अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान-रूस गठबंधन भारत तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। दोनों ही देश मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रूस अपने मध्य एशियाई दायरे में स्थिरता चाहता है और इस क्षेत्र के प्रबंधन में पाकिस्तान महत्वपूर्ण बना हुआ है। इस्लामाबाद तक मास्को की पहुंच क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता से (भरपूर) लाभ उठाने का एक प्रयास है।

चूंकि नई दिल्ली मास्को के साथ विशेष संबंध साझा करता है, इसलिए रूस-पाकिस्तान नजदीकियों के कारण कुछ बेचैनी पैदा हो गई है। तथापि, मास्को के विशेषज्ञ बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ रूस का रक्षा करार भारत की कीमत पर नहीं होगा। भारत में भी विशेषज्ञों की राय है कि रूस द्वारा भारत के साथ अपने विशाल रक्षा व्यापार को खतरे में डालकर कुछ भी किए जाने की संभावना नहीं है। इसी प्रकार, जहां तक पाकिस्तान को अनुदान और रक्षा सहयोग दिए जाने का संबंध है, मास्को कभी भी वाशिंगटन का स्थान नहीं ले सकता। पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर पाने में यह अत्यंत लाचार है।

पाकिस्तान-रूस संबंध हाल के महीनों के दौरान सकारात्मक दिशा में विकसित होते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। चूंकि दोनों पक्षों ने नए क्षेत्रों की तलाश करने तथा अनेक क्षेत्रों में पहले से मौजूद/जारी सहयोग सुदृढ़ करने में गहरी रूचि दिखलाई है, इसलिए आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग में विस्तार देखा जाना तय है। ऊर्जा, क्षेत्रीय संपर्क, बुनियादी सुविधाएं और व्यापार के क्षेत्र इन प्रयासों के केन्द्र में रहने वाले हैं। तथापि, दोनों देशों के बीच नई उभरती इस दोस्ती पर नई दिल्ली-वाशिंगटन द्वारा बारीकी से नजर रखे जाने की संभावना है।

*_डॉ. स्मिता तिवारी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।_